# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—२ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि २८ जुलाई, १९८१ ई० ।

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| अध्यक्षीय घोषणा : | |
| निर्दलीय सदस्य का कांग्रेस (आई) दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में । | १ |
| शून्यकाल की चर्चाएँ : | |
| (क) कुमारखुम्बी इंजीनियरिंग वर्क्स का राष्ट्रीयकरण ... | १—२ |
| (ख) टिकुलिया हाट के नजदीक श्री जगदीश प्रसाद की हत्या ... | ३ |
| (ग) बासोपट्टी एवं हरलाखी थाना में हत्या एवं डकैती की घटनाएँ । ... | ४ |
| (घ) सुलतानगंज से लेकर देवघर तक विद्युतीकरण की व्यवस्था ... | ४ |
| (ङ) गिरिडीह कालेज में भवन, बस आदि का अभाव .... | ४—५ |
| (च) माईका के मजदूरों को महंगाई भत्ता का भुगतान ... | ५ |
| (छ) बगहा अनुमंडल के श्री विरेन्दरी पाण्डेय की हत्या ... | ५—६ |
| (ज) हायाघाट प्रखंड में वर्षा एवं बाढ़ से जननीवन ठप्प ... | ६—७ |
| ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य : | |
| (अ) इन्टरमीडिएट एवं बी० ए० (पास) कोर्स का केन्द्र जिला मुख्यालयमें रखा जाना । | ७—१० |

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि २८ जुलाई, १९८१ ई० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकल विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २८ जुलाई, १९८१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

## अध्यक्षीय घोषणा :

अध्यक्ष —श्री रामवृक्ष चौधरी, स०वि०स० निर्वाचन क्षेत्र संख्या ७२ (पुपरी) जो निर्दलीय सदस्य थे, निर्दलीय सदस्य का कांग्रेस (आई) दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचित किया है कि वे कांग्रेस (आई) विधायक दल में सम्मिलित हो गये हैं ।

## शून्य-काल की चर्चाएँ :

### (क) कुमारडुबी इंजीनियरिंग वर्क्स का राष्ट्रीयकरण ।

*श्री अब्दुल गफूर—अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस के अन्दर मौजूद हैं । एक निहायत अहम मसले की तरफ आपके जरिये इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । सभी लोग जानते हैं कि २८ तारीख से हमारे एक विधायक अनशन पर हैं, यह अनशन सही है या नहीं, इसपर हमको बोलना नहीं है, लेकिन चटर्जी साहब अनशन पर हैं । आपके जरिये हमको यह खबर कर देना है, ये जानते हैं कि पिछली दफा यह सवाल उठा था हाउस के अन्दर, जिसमें उन्होंने एक किताब बंटवायी थी कि कुमारडबी इंजीनियरिंग फैक्ट्री को चलाने जा रहे हैं, कुछ हमारे कांग्रेस (आई) के मित्र लोगों ने, जिनका नाम हम अभी नहीं लेना चाहते, वे लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी से भी मिले थे और शायद

उन्होंने भी ऑर्डर किया है कि इसको चलाना चाहिए। अब यह कहां पर जाकर अटका हुआ है, यह हमको पता नहीं है। इसी दरम्यान उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। एक चीज और हम खास तौर से बता देना चाहते हैं कि कलत्ता उच्च न्यायालय ने इधर एक जजमेंट दिया है, इसकी तिथि मुझे अभी मालूम नहीं है, दो-तीन हफ्ता टाइम दिया है कि इस दरम्यान सरकार अगर फेल हो जाती है उस फैक्ट्री को चलाने में तो वैसी हालत में सारी फैक्ट्री नीलाम कर दी जायगी। आज के अखबार को देखा है कि यहां के मिनिस्टर ने निकाला है कि इन्डस्ट्रीयलिस्ट लोग यहां आये। एक इतनी बड़ी फैक्ट्री, सभी लोग जानते हैं कि ११ करोड़ रुपये का ईरान से इसको ऑर्डर मिला था वहां का काम बनाने के लिये, लेकिन ऑर्डर मिलने के थोड़े ही दिनों बाद ईरान-इराक की लड़ाई शुरू हो गयी और इसी दरम्यान यह गड़बड़ी शुरू हो गयी।

हम इस केस में दिल्ली जाकर उस वक्त के मिनिस्टर जो थे, उनसे और वहां के पदाधिकारियों से हमारी बातें हुई थीं और उन लोगों ने भी कहा था कि इसको देख-भाल करके चलाने की कोशिश करेंगे।

इस हाउस के अन्दर हम तमाम मेम्बरों को बतला देना चाहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान के ट्रेड यूनियनों ने आजतक किसी ने ऐसा नहीं किया कि लगभग दो करोड़ रुपया वहां के वरकर्स का बकाया है, जिसके संबंध में वरकर्स ने लिखकर दिया है कि हम इसका डिमाण्ड नहीं करेंगे, वहां के वरकर्स ने यह भी कहा है कि सरकार फैक्ट्री चलाये, हम सरकार को मदद करने के लिए पांच साल तक किसी किस्म की हड़ताल नहीं करेंगे।

ये सारी चीजें हैं, ऐसी हालत में मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये अगर कुछ आश्वासन दें तो हम जाकर चटर्जी साहब से उसे कहें।

अध्यक्ष—हम शून्य-काल में सरकार को कुछ कहने के लिये बाध्य नहीं करते हैं। इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना भी आयी थी। सरकार का जवाब बड़ा सहानुभूतिपूर्वक था। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जिस संदर्भ में उन्होंने ध्यानाकर्षण में कहा था, उससे सम्बन्धित विषय पर ३.३० या ४ बजे अपराह्न में एक स्टेटमेंट सरकार को दे दें।